आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए विशेष विपणन सुविधाएं

579. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषकों को, अपना उत्पादन अपने आप बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ होने के कारण या बाजार पर उनका कोई नियंत्रण न होने के कारण, मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में अपना कृषि उत्पादन बिचोलियों और व्यापारियो को बहुत कम मूल्यों पर बेचना पड़ता है जबकि उपरोक्त वस्तुओं का वास्तविक मूल्य बहुत अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अविकसित क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रो मे कृषि उत्पादन के लिए विपणन की विशेष व्यवस्था करने की दशा में कोई नई पहल कर रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान में जो सहकारी समितियां वहां पर कार्य कर रही हैं व अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हुई हैं; यदि हां, तो क्या उक्त समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में घाटे की बिक्री की कोई विशेष घटना भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, उत्पादकों में अपनी फसल को रोके रखने की कम क्षमता, क्षेत्र में यातायात साधनो की कमी, भण्डारण सुविधाओं और विपणन ढांचे के अभाव के कारण कृषि उपज की घाटे पर बिक्री हो सकती है।

(ख) भारत सरकार कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं के अनुमोदन के समय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) संविधान के अन्तर्गत "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। किसानों की सहायता करने के लिए सहकारी समितियों को अधिक प्रभावकारी ढंग से सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को ई०एस०आई० योजना का लाभ दिया जाना

580. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत बीड़ी मजदूरों को अभी तक ई०एस० आई० योजना का लाभ नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अधीन सभी बीड़ी मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए क्या पहल की जा रही है;

(ग) देश के अन्य प्रदेशों में कार्यरत बीड़ी मजदूरों की क्या स्थिति है; और

(घ) क्या सरकार मजदूरों को उपरोक्त योजना का लाभ देकर शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है क्योंकि अधिकांश बीड़ी मजदूर समाज के सर्वहारा वर्ग के हैं?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) क० रा० बी० योजना को क्षेत्र-वार श्रमिक ढंग से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीड़ी का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान, जो बिजली का प्रयोग करते हैं तथा 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और ऐसे प्रतिष्ठान जो बिजली